ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-11*December- 2021
Innovation The Research Concept

भारत नेपाल सम्बन्ध घनिष्टता से कटुता की ओर
India Nepal relations from closeness to Bitterness

Paper Submission: 10/12/2021, Date of Acceptance: 21/12/2021, Date of Publication: 22/12/2021

अनिता कुमारी
शोधार्थी,
दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

नेपाल-भारत के संदर्भ में जूनियर भागीदारी के मनोविज्ञान से ग्रसित है तथा दक्षिण के पड़ौसी के आधिपत्य की आशंका का भूत उसे सताता रहता है। नेपाल भारत और चीन के साथ समदूरी सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्ध विकसित करना चाहता है जिससे चीन को भी संतुष्ट किया जा सकें परन्तु भारत समदूरी सिद्धान्त को नहीं मानता, यह तो नेपाल के साथ विशिष्ट सम्बन्ध चाहता है, उसका कहना है कि नेपाल एक आतंरिक देश है। अतः उसके साथ भारत के विशिष्ट सम्बन्ध रहना स्वाभाविक है।

In the Nepal-India context, Junior is haunted by the psychology of participation and haunts him with the fear of hegemony from the neighboring south. Nepal wants to develop relations with India and China on the basis of equidistant principle.So that China can also be satisfied, but India does not accept the equidistant principle, it wants a special relationship with Nepal, it says that Nepal is an internal country. Therefore, it is natural for India to have special relations with him.

मुख्य शब्दः 1950 की मैत्री संधि, मधुरता और सामंजस्य, प्रजातांत्रिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक सम्बन्ध।

Keywords: Friendship Treaty of 1950, Sweetness And Harmony, Democratic, Political, Economic, Strategic Relations.

प्रस्तावना

दक्षिणी एशिया में भारत केन्द्रीय स्थिति रखता है। भारत के चारों ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालद्वीप स्थित है। भारत को मिलाकर यह 8 देश एशिया के क्षेत्रीय संगठन सार्क के भी सदस्य है। भारत के अपने सभी पड़ौसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध है। भारत और उसके पड़ौसी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समस्या से ग्रस्त रहे है। भारत स्थायी और सुरक्षित पड़ौसी चाहता हैं, जो उसकी सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी देश तब तक न तो अपना विकास कर सकता है और न अपने को सुरिक्षत महसूस कर सकता है जब तक कि उसके पड़ौसी देश राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है। भारत के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है, क्योंकि भारत के चार पड़ौसी देश अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश अल्पविकसित देशों में आते है। इनके अतिरिक्त अन्य देश भी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि समस्याओं से ग्रस्त है, भारत अपने पड़ौसी देशों के प्रति सहयोग और मित्रता की नीति का पालन करता है।

सर्व प्रथम यह समझ लेना आवश्यक है कि नेपाल एक भूवेष्टित राज्य है जिसके उत्तर में विशाल हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो विशाल हिमालय के नाम से जानी जाती है और उसके दक्षिण मंे एक विशाल देश भारतवर्ष है। हिमालय पर्वत के उत्तर में भारतवर्ष से भी बड़ा राज्य चीन स्थित है और नेपाल को सदैव यह चेतना बनी रही है कि वह भ्ूामि की दृष्टि से दो विशाल राज्यों के मध्य स्थित है और वह इनमें से किसी को भी अप्रसन्न नहीं कर सकता है। नेपाल के लिए दोनों ही राज्य महत्वपूर्ण है और वह किसी की भी उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं है। न ही वह किसी को अप्रसन्न कर सकता है। वह दो पार्टियों के मध्य फंसा हुआ है और इसलिए उसे हर कदम फंूक-फूंक कर रखना पड़ता है। इन दोनों देशों में किसी की भी अप्रसन्नता महंगी सिद्ध हो सकती है।

अंग्रेज जब भारतवर्ष आये और भारतीय अर्द्ध महाद्वीप पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया तो इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने इसके चारों ओर ऐसी घेराबंदी करली कि किसी भी ओर से शत्रु भारतवर्ष पर आक्रमण न कर सके। इस दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रखते हुए अंग्रेजों ने सामरिक दृष्टि के कुछ नीतिगत निर्णय लिए जिनमें प्रमुख था भारतवर्ष के बाहर चारो ओर अपना प्रभाव स्थापित करना। यह सोचकर उन्होंने दक्षिण में श्रीलंका पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और पूर्व में बर्मा पर आधिपत्य किया। उत्तर में अफगानिस्तान और तिब्बत से सीमा समझौता किया ताकि इस ओर से भी भारत की सीमाएँ सुरक्षित रहे। परन्तु सिक्किम, भूटान एवं नेपाल वाले हिमालय क्षेत्र के छोटे राज्यों को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों कि इनसे भारत को कोई खतरा नहीं था। इस कारण अंग्रेजों के नेपाल से सम्बन्ध सहयोगपूर्ण रहे और द्वितीय महायुद्ध में नेपाल के गोरखा सैनिक मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़े और उन्होंनें अनुपम वीरता एवं शौर्य का प्रदर्शन किया। इस प्रकर अंग्रेजों के शासनकाल में भारत-नेपाल सम्बन्ध अति मधुर और सहयोगपूर्ण बने रहे। परन्तु सन् 1947 में जब भारतवर्ष स्वाधीन हुआ तो स्थिति परिवर्तित होने लगी। भारत एक प्रजातांत्रिक देश बना। नेपाल में निरंकुश राजतंत्र था। भारत की प्रारम्भ से ही प्रजातांत्रिक राज्यों की सहायता करने की नीति थी और इस कारण नेपाल के साथ सम्बन्धों में मधुरता के अभाव की आशंक बनी हुई थी।

भारतवर्ष की प्रजातांत्रिक राष्ट्रों के समर्थन की नीति उसके और नेपाल के सम्बन्धों को बिगाड़ सकती थी परन्तु स्वतंत्रता के प्रारम्भिक चरणों में ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि नेपाल नरेश त्रिभुवन केवल एक प्रकार का मुखौटा था और वास्तविक सत्ता वहां राणा प्रशासकों के हाथ में थी जो सम्राट का उपयोग एक रबड़ की मोहर की तरह करते थे और धीरे धीरे सम्राट की स्थिति इतनी सोचनीय हो गई कि उसे नेपाल से पलायन कर भारत में शरण लेनी पड़ी। ये थे सम्राट त्रिभुवन। क्योंकि काफी समय तक वे भारत के मेहमान थे और भारत सरकार के प्रयासों से ही उन्हें नेपाल का सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ था। इस कारण वे भारत सरकार के प्रति कृतज्ञ थे। और उन्होंने भारत से सुमधुर सम्बन्ध बनाये रखे।

भारत-नेपाल सम्बन्ध महाराजा त्रिभुवन के समय में तो सुमधुर बने रहे परन्तु उनके देहावसान के बाद नये नरेश महेन्द्र के समय सम्बन्धों में गिरावट आनी प्रारम्भ हो गई जो स्वाभाविक थी। सम्राट महेन्द्र स्वभाव से अप्रजातांत्रिक थ्े और उन्होंने नेपाल में प्रजातंत्र के समाप्त कर अपना प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया था। उधर स्थिति यह थी कि नेपाल में जो कुछ प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनी थी वह भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप थी और इसलिए नेपाल के सम्राट महेन्द्र ने वहां प्रजातंत्र समाप्त किया तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सहित सभी ने इसकी आलोचना की तथा भारतीय समाचार पत्रों में भी इसके विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां की गई। यह महाराज महेन्द्र के अरूचिकर प्रतीत हुआ और उन्हें अप्रसन्न करने हेतु पर्याप्त था। उनके कदमों की भारत द्वारा आलोचना उनके लिए असह्य थी और वे इसे नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा देश की स्वतंत्रता व सार्वभौमिकता पर आघात एवं प्रहार मानते थे। परिणाम यह हुआ कि जितनी भारत में नेपाल सरकार की आलोचना होती गई उतने ही भारत-नेपाल सम्बन्ध बिगड़ते गये।

भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 मंे दोनों राष्ट्रों के मध्य विशिष्ट सम्बन्धों का उल्लेख किया गया था जो कालान्तर में दोनों राष्ट्रों के मध्य विवााद का विषय बन गई। धीरे-धीरे नेपाल में यह धारणा बनती गई कि विशिष्ट सम्बन्ध एक प्रकार से उसकी भारत पर निर्भरत एवं आत्मसमर्पण का प्रतीक है। और इससे उसकी स्वाधीनता और सार्वभौमिकता को आघात लग रहा है और उससे भावात्मक रूप से अपूर्णीय क्षति हो रही है।

भारतवर्ष में समाजवादी दल के नेता जिनमें जय प्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया प्रमुख थे, के सम्बन्ध सदैव नेपाली कांग्रेस के नेताओं से घनिष्ठ रहे थे और उनके द्वारा की गई नेपाल सरकार के विरूद्ध टिप्पणियां नेपाल में सदैव विवाद क विषय बनी रही अैर दोनों देशों के मध्य वैचारिक दरार को बढ़ाने में सहायक रही।

नेपाल की जनता में सदैव एक पक्ष ऐसा रहा है जो स्वभाव से भारत विरोधी था और वह भारतवर्ष को विस्तारवादी समझता रहा है। उन्हें भारत की प्रत्येक नीति में भारत का छल एवं छद्म दिखता था और उनको भय था कि भारत नेपाल को सहयोगी राष्ट्र न मानकर एक निर्बल राज्य मानता था जिसको दबाने की वह भरसक कोशिश करत रहा है।

नेपाल और भारत सम्बन्धों में सर्वाधिक कड़वाहट इस बात को लेकर हुई कि जो राज्य विरोधी नेपाली अपने देश से पलायन कर भारत आ गये। भारत उनकी शरण स्थली बन गया और उन्हें नेपाल विरोधी कार्यों में सहयोग देने लग गया। नेपाल का आरोप था कि भारत में रहकर ये लोग न केवल नेपाल के विरूद्ध दुष्प्रचार कर रहे थे अपितु नेपाल में तोड़फोड़ की हिंसात्मक गतिविधियों में भी ये लोग लिप्त थे। इसके अतिरिक्त नेपाल में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से इन्होंने भारी मात्रा में अवैध हथियार एकत्रित कर रखे थे जिनका दुष्प्रयोग नेपाल में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा था। नेपाल ने बार-बार यह आरोप लगाया कि भारत सरकार की सहायता बिना नेपाल विरोधी अपने कार्य कलापों में कभी सफल नहीं हो सकते थे। नेपाल जानना चाहता था कि नेपाल विरोधियों के पास प्रचार सामग्री और शस्त्रों की खरीद के लिए कौन सहायता कर रहा था ? भारतवर्ष के पास इस प्रकार के आरोप का औपचारिक खण्डन करने एवं इन्हें निराधार बताने के अतिरिक्त कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था जो इन सम्बन्धों को और बिगाड़ने में सहायक हुए।

सन् 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की पराजय के पश्चात् भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यन्त क्षीण हो गई और पहली बार भारत को ज्ञात हुआ कि पड़ौसियों के साथ सम्बन्ध सुधारने की नीति ही हितकर होती है न कि उनके विरोधियों की सहायता कर सम्बन्ध बिगाड़ने की नीति। इस युद्ध एवं इसमें हुई पराजय से भारत ने सही सबक लिया

जहां एक ओर सन् 1962 में चीन से हुए युद्ध में भारत की पराजय ने उसे प्रभाव को अत्यन्त कम कर दिया तत्पश्चात् सन् 1971 में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश के निर्माण से भारत की शक्ति इतनी बढ़ गई कि नेपाल का भयभीत होना स्वाभाविक था। यह भय और भी बढ़ गया जब भारत ने सिक्किम का अपने अंदर विलय कर लिया और परमाणु परीक्षण क रवह एक आणविक शक्ति बन गया। जितनी भारत की सामरिक शक्ति बढ़ती गई नेपाल उतना ही भयभीत होता गया और इसलिए उसने चीन एवं पाकिस्तान से अपने मैत्री सम्बन्ध बढ़ा कर भारत की शक्ति के सन्तुलित करने का प्रयास किया।

भारत नेपाल के मध्य एक और विवाद नेपाल के उत्तरी क्षेत्र में सैनिक चौकियांे को लेकर बना हुआ था जिन्हें नेपाल हटाना चाहता था परन्तु भारत इसके लिए सहमत नहीं था। नेपाल काठमाण्डु स्थित भारतीय

सैनिक शिष्ट मंडल को भी वापिस भेजना चाहता था परन्तु भारत ने कुछ सैनिक किसी अन्य नाम से रख रखे थे जिसे लेकर भारत और नेपाल के मध्य विवाद बना हुआ था।

सन् 1962 के पश्चात् भारत ने पड़ौसियों के साथ अपने सम्बन्धों में अनेक सार्थक परिवर्तन किये परन्तु फिर भी छोटे-छोटे विवाद कभी अप्रत्याशित रूप से बड़े हो जाते हैं और परस्पर विवादों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनमें नेपाल में प्रवाहित होने वाली नदियों को लेकर भी विवाद है। नेपाल के साथ सम्बन्ध सुधारने का सर्वाधिक श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाता है परन्तु यह कहना कठिन है कि वह सब कुछ ईमानदारी से सम्बन्ध सुधारने का एक सम्मुनत प्रयास था या जनता पार्टी सरकार की आंतरिक दुर्बलता। क्योंकि जनता पार्टी सरकार में एकता व अनुरूपता का नितान्त अभाव था और इसलिए यह संभव है कि दल के एक घटक जनसंघ क एक व्यक्ति भारत का विदेश मंत्री बने तो स्वभावतया नेपाल के दृष्टिकोण का पक्षधर एवं सार्थक रहेगा। जनसंघ ने अपनी हिन्दुवादी नीति के कारण नेपाल के साथ सम्बन्ध सुधारे हों क्योंकि उनके अनुसार नेपाल विश्व का एकमात्र हिन्दू साम्राज्य रहा है।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया, जिसमें पड़ौसियों के साथ सम्बन्धों को नई दिशा दी। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने पड़ौसी देशों से सम्बन्ध में कुछ नियम बताए जिसे गुजराल सिद्धान्त कहा जाता है।

2005 में भारत ने अपनी नई पड़ौस नीति की घोषणा की जिसमें भूमण्डलीकरण के युग में क्षेत्रीय एकता को आवश्यक माना गया। भारत की नई पड़ौस नीति के मुख्य बिन्दू निम्नवत् हैः-

भारत अपने बोर्डर एरिया को अनदेखा नहीं करेगा, वह अपने उन क्षेत्रों का विकास करेगा जिसकी सीमा पड़ौसी देश की सीमा से मिलती है।

1. भारत की पड़ौस नीति का मुख्य तत्व यह है कि भारत अपने अधिकतम प्रयासों से इस क्षेत्र का विकास करेगा, इसके लिए वह लोगों को सुविधाऐं उपलब्ध करवायेगा।
2. भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों के साथ सांस्कृतिक तथा लोगों के मेल-जोल को प्रोत्साहित करेगा।

नेपाल एक ऐसा पड़ौसी देश है जिसके साथ भारत ने वीजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अतः दोनों देशों के बीच बिना वीजा के ही नागरिक आ जा सकते है। भारत के उŸार में स्थित नेपाल एक भूमि से घिरा देश है। भारत नेपाल सीमा रेखा 1850 किलोमीटर लम्बी है। भारत के लिए नेपाल की स्थिति सामरिक महत्व की है, क्योंकि नेपाल दो बड़े देशों भारत और चीन के बीच एक मध्यस्थ राज्य के रूप में स्थित है। नेपाल की सरकारों में इस स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत के विरूद्ध चाईना कार्ड खेलने का प्रयास किया। यह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील मामला है। जब भारत अपने सुरक्षा हितों को लेकर इस सम्बन्ध में कोई प्रयास करता है तो नेपाल उसे अपने आन्तरिक हस्तक्षेप के रूप में देखता है। दोनों देशों के बीच यह मुद्दा कई बार मतभेद का कारण बन चुका है। नेपाल में चल रही वर्तमान उथल-पुथल तथा राजनीति में माओवादी तत्वों के बढ़ते प्रभाव के कारण यह मामला फिर महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि नेपाल के माओवादी चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों के पक्षधर है।

जहाँ तक भारत-नेपाल के राजनीतिक सम्बन्धों की बात है तो भारत नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना का पक्षधर है, लेकिन वर्तमान में नेपाल में माओवादी दल को अन्य दलों की तुलना में अधिक समर्थन प्राप्त है। नेपाल की राजनीति में माओवादियों का प्रभुत्व एक नया तत्व है जिसका आकंलन भारत नहीं कर पाया। परिणामतः नेपाल की माओवादी पार्टी के नेता पुष्पकमल दहल 'प्रचंण्ड' ने 2008 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद भारत आने से पहले चीन की राजकीय यात्रा की। ऐसा नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेपाल के राजनीतिक दलों में नेपाली कांग्रेस के साथ भारत के घनिष्ठ रिश्ते रहे है। अब माओवादियों ने भारत पर नेपाल के आतंरिक मामलों पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इसका अन्य पहलू यह है कि भारत में सक्रिय नक्सलवादी, माओवादी समूह के साथ भी नेपाल के माओवादियों के सम्बन्ध विकसित हो चूके है, यह भारत की आतंरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक संवेदनशील मामला है नेपाल में अभी राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान है तथा 2008 में राजशाही की समाप्ति तथा गणतंत्र की स्थापना के बाद भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में प्रमुख राजनीतिक दलों में अब भी गम्भीर मतभेद है तथा नेपाल राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। 2005 में भारत ने विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समझौता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उनके बीच जो समझौता सम्पन्न हुआ था उसपर हस्ताक्षर नई दिल्ली में ही किये गये। नेपाल की वर्तमान सरकार व वैचारिक तौर पर भारत की अधिक नजदीक है लेकिन फिर भी चीन नेपाल के सम्पर्क सूत्रों के विकास का भी प्रयास कर रहा है लेकिन औपचारिक रूप से नेपाल सरकार भारत व चीन के बीच समान दृष्टिकोण अपनाने का दावा करती है। अतः दोनों देशों के बीच राजनीतिक सम्बन्धों का भविष्य नेपाल में उभरती हुई राजनीतिक व्यवस्था व प्रजातंत्र के भविष्य पर निर्भर करता है।

नेपाल-भारत सम्बन्धों में मधुरता एवं सामंजस्य की कमी का एक कारण कदाचित राजनीतिक व्यवस्था का अंतर भी हो सकता है जहां भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक राज्य रहा है। नेपाल कुछ वर्षों पूर्व तक एक राजतंत्र रहा है और अब पहली बार वहां राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया है। परन्तु यह भी उतना सफल नहीं हुआ है जितना भारत चाहता था। नेपाल के माओवादी नेपाल के चीन के साथ अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध चाहते हैं और यह इस बात को स्पष्ट कर देता है कि भारत

नेपाल सम्बन्धों को बिगाड़ने में अप्रत्यक्ष रूप से चीन की भी महत्ती भूमिका रही है जिसने नेपाली जनमत के एक भाग को अपनी ओर आकर्षित कर उसे भारत विरोधी बना रहा है। भारतवर्ष को भी नेपाल के चीन के साथ बढ़ते हुए सम्बन्ध आशंकित करते हैं और इस कारण भी दोनों राष्ट्रों के मध्य यदा कदा सम्बन्धों में मधुरता की कमी आ जाती है।

उद्देश्य

1. रत-नेपाल संबंधों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 21 वीं सदी तक आये बदलावों का अध्ययन करना।
2. 21 वीं सदी में भारत-नेपाल सम्बन्धों मे उभर रही नयी प्रवृर्तियों पर प्रकाश डालना।
3. भारत-नेपाल संबंधों का दक्षिण एशिया के देशों के संदर्भ में मूल्यांकन।
4. भारत व नेपाल के सीमावर्ती राज्य के साथ उनके संबंधों व सीमा विवादों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना।
5. दक्षिण एशिया की सामरिक व सुरक्षात्मक चुनौतियों के संदर्भ में भारत-नेपाल संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
6. नेपाल में शांति स्थिरता में भारत के योगदान का मूल्यांकन करना।
7. नेपाल में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में भारत की भूमिका अवलोकन करना।

निष्कर्ष

वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देशों के सम्बन्धों की आधारशीला के प्रति अविश्वास के कारण दोनों के सम्बन्ध तनावपूर्ण हुए भारत को ऐसा प्रतीत हुआ कि नेपाल उसके सुरक्षा हितों को अनदेखा कर रहा है। जबकि नेपाल अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के प्रति अधिक चिन्तित था। वह भारत से अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता था जबकि 1950 की मैत्री संधि के नवीनीकरण, चीन से अस्त्र शस्त्र के आयात आदि प्रश्नों को उठाकर उसने भारतीय हितों को अनदेखा करना प्रारम्भ कर दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी व महाराजा वीरेन्द्र के बीच व्यक्तित्व के टकराव के कारण भी पारस्परिक संदेह बढ़ा तथा विवादित मुद्दों को हल करने में कठिनाई उत्पन्न हुई लेकिन 1990 से भारत में राजनीतिक परिवर्तन तथा नेपाल में लोकतंत्र की सफलता के साथ ही संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई।

सदर्भ ग्रंथ सूची

1. *बी.सी. उप्रेती, स्टेट एण्ड डेमोक्रेसी इन नेपाल, 2011*
2. *निर्मला अग्रवाल, भारत नेपाल सम्बन्ध, 2003*
3. *डॉ. अशु पाण्डे भारत नेपाल सम्बन्ध, 2004*
4. *डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, भारत नेपाल सम्बन्ध, 2011*
5. *एस.डी. मूनि, इण्डिया एण्ड नेपाल, 1992*
6. *बालचन्द्र शर्मा नेपाल की ऐतिहासिक रूपरेखा*
7. *डॉ. शिव बहादूर सिंह, नेपालः शासन और राजनीति, 2000*